12-05-2023

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

समाचार पत्रों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) की एक नई रिपोर्ट में पाया गया है कि वर्ष 2015 के बाद से प्रत्येक वर्ष गर्भावस्था, प्रसव या जन्म के पहले सप्ताह के दौरान मरने वाली महिलाओं और शिशुओं की संख्या में आ रही कमी में बाधा उत्पन्न हुई है।

त्वरित मुद्दा?

- रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत मातृ मृत्यु, स्टिलबर्थ/मृत जन्म और नवजात मृत्यु के वैश्विक बोझ में सबसे आगे है, जो कुल मृत्यु का 17% है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- भारत के बाद वर्ष 2020 में सबसे अधिक निरपेक्ष मातृ और नवजात मृत्यु तथा मृत जन्म वाले देश नाइजीरिया, पाकिस्तान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान एवं तंज़ानिया हैं।
- रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों से पता चलता है कि वर्ष 2000 और 2010 के बीच हुए सुधार वर्ष 2010 के बाद के वर्षों की तुलना में तेज़ थे, साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अगले दशक में यह कैसा होना चाहिये।
- मातृ मृत्यु दर अनुपात (Maternal Mortality Ratio- MMR):MMR में वर्ष 2000 और 2009 के बीच 2.8% की दर से वार्षिक कमी देखी गई, जो वर्ष 2010 एवं 2020 के बीच घटकर 1.3% हो गई है।
- मातृ मृत्यु अनुपात किसी दी गई जनसंख्या या क्षेत्र में प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है।
- प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 70 मौतों के MMR के वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अगले दशक में इस सूचक को 11.9% तक कम करने हेतु सुधार की आवश्यकता है।
- **स्टिलबर्थ रेट (SBR):-** SBR वर्ष 2000 और 2009 के बीच 2.3% एवं वर्ष 2010 और 2021 के बीच 1.8% कम हो गया था।प्रति 1,000 जन्मों पर ऐसे बच्चों का जन्म जिनके विषय में गर्भावस्था के 28 सप्ताह अथवा उसके बाद के समय में भी बच्चे के विषय में कोई संकेत नहीं मिल रहे होते हैं, SBR कहा जाता है।
- वर्ष 2022 और 2030 के बीच प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 12 से कम मृत जन्मों के वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने के लिये 5.2% की दर से इस प्रकार की मौतों में कमी लाने की आवश्यकता है।
- **मातृ मृत्यु:**
  - **अधिक रक्तस्राव:-** यह मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण है, जो अक्सर बच्चे के जन्म के दौरान अथवा तत्काल प्रसवोत्तर अवधि में होता है।

- **उच्च रक्तचाप विकार (प्री-एक्लेमप्सिया और एक्लम्पसिया):** इन स्थितियों के परिणामस्वरूप अंग विफलता, दौरा पड़ना और यहाँ तक कि मातृ मृत्यु भी हो सकती है।
- **असुरक्षित गर्भपात:** ऐसे क्षेत्र जहाँ सुरक्षित और कानूनी गर्भपात तक पहुँच सीमित है, महिलाएँ असुरक्षित प्रक्रियाओं का सहारा लेती हैं जिससे कई जटिलताएँ और मातृ मृत्यु हो सकती है।
- **अन्य कारक:** मोटे तौर पर एक-तिहाई महिलाएँ अनुशंसित आठ प्रसव-पूर्व जाँचों में से चार भी नहीं करवाती हैं या फिर उन्हें आवश्यक प्रसवोत्तर देखभाल प्राप्त नहीं होती है, लगभग 270 मिलियन महिलाओं की आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुँच नहीं है।

- **शिशु मृत्यु:**
  - **जन्म के समय वज़न कम होना:-** अतिशीघ्र (समय से पूर्व/प्रीटर्म) या जन्म के समय कम वज़न वाले बच्चे विभिन्न स्वास्थ्य जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उनमें मृत्यु दर का खतरा अधिक होता है।
  - **बर्थ एस्फिक्सिया (जन्म के समय दम घुटना):** जब बच्चे को प्रसव के दौरान पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो इसका परिणाम बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, यदि तुरंत उपचार नहीं किया जाता है तो मस्तिष्क क्षति या मृत्यु हो सकती है।
  - **आकस्मिक शिशु मृत्यु सिंड्रोम (SIDS):** SIDS एक वर्ष से कम उम्र के शिशु की आकस्मिक, अस्पष्टीकृत मृत्यु को संदर्भित करता है, यह सामान्यतः नींद के दौरान होती है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से संबंधित सरकारी पहलें

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK): भारत सरकार ने 1 जून, 2011 को यह योजना शुरू की है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन सेक्शन सहित बिल्कुल मुफ्त और बिना किसी खर्च के प्रसव कराने का अधिकार देती है।
- यह पहल नि:शुल्क दवाओं, निदान, रक्त और आहार के अतिरिक्त घर से संस्था तक नि:शुल्क परिवहन जैसे- घर से ले जाने और वापस छोड़ने की सुविधाएँ निर्धारित करती है। वर्ष 2013 में इसे बीमार शिशुओं और प्रसव-पूर्व एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं तक विस्तारित किया गया था।
- जन्म के 30 दिन बाद तक इलाज के लिये सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुँचने वाले सभी बीमार नवजातों को इसी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA): इसे वर्ष 2016 में प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं में गुणवत्तापूर्ण प्रसव-पूर्व देखभाल और उच्च जोखिम गर्भावस्था का पता लगाने हेतु प्रारंभ किया गया था।
- **लक्ष्य:** आने वाले वर्षों में MMR (मातृ मृत्यु दर) में और गिरावट लाने के लिये सरकार ने 'लक्ष्य- लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव' लॉन्च किया है।
- लक्ष्य कार्यक्रम लेबर रूम और मातृत्व ऑपरेशन थिएटर से संबंधित प्रमुख प्रक्रियाओं को मज़बूत करने के लिये एक केंद्रित और लक्षित दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य जन्म के समय देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल सुनिश्चित करना है।

ट्रॉपिक्स मिशन

समाचार पत्रों में क्यों?

न्यूज़ीलैंड में मौसम की गड़बड़ी के कारण अप्रैल में प्रारंभिक लॉन्च को रद्द करने के बाद हाल ही में नासा और रॉकेट लैब ने कक्षा में तूफान-ट्रैकिंग के लिए सफलतापूर्वक दो क्यूबसैट लॉन्च किए।

त्वरित मुद्दा?

- मिशन TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats) के लिए दो घंटे की लॉन्च विंडो थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- ट्रॉपिक्स एक ऐसा मिशन है जिसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को देखने के उद्देश्य से चार समान क्यूबसैट शामिल हैं। ये क्यूबसैट पारंपरिक मौसम ट्रैकिंग उपग्रहों की तुलना में अधिक बार डेटा एकत्र करेंगे।
- रॉकेट लैब द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल लॉन्च वाहन का उपयोग करके पहले दो उपग्रह लॉन्च किए गए थे। इन उपग्रहों का दूसरा सेट लगभग दो सप्ताह में प्रक्षेपित किया जाएगा।
- क्यूबसैट पारंपरिक मौसम ट्रैकिंग उपग्रहों से उस आवृत्ति में भिन्न होते हैं जिस पर वे अवलोकन करते हैं। अधिक बार डेटा एकत्र करने से वैज्ञानिक अपने मौसम के पूर्वानुमान में सुधार कर सकते हैं।
- ट्रॉपिक्स की अवलोकन प्रणाली लगभग वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए पर्यावरणीय और आंतरिक-कोर स्थितियों को मापने के लिए क्षैतिज और अस्थायी रेजोल्यूशन का एक अभूतपूर्व संयोजन प्रदान करती है, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करती है।

आईड्रोन पहल

समाचार पत्रों में क्यों?

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की आईड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

त्वरित मुद्दा?

- परियोजना 'आई -ड्रोन' (आईसीएमआर का ड्रोन रिस्पांस एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट) ने टीके और चिकित्सा आपूर्ति देने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की व्यवहार्यता का आकलन किया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- यह ट्रायल रन क्षेत्र भूमि, द्वीप, तलहटी और पहाड़ियों सहित कठिन भौगोलिक इलाकों में किया गया था।
- आईसीएमआर द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान अगम्य क्षेत्रों में टीकों के वितरण के लिए पहली बार 'आई-ड्रोन' का उपयोग किया गया था।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और प्रचार के लिए भारत में शीर्ष निकाय हैं।

- ICMR को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।
- परिषद के शासी निकाय की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करते हैं।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 27वीं बैठक का आयोजन किया गया।

त्वरित मुद्दा?

- केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
- बैठक में वित्तीय सुविधाओं तक जनता की पहुंच बढ़ाने बल्कि उनकी समग्र आर्थिक बेहतरी के लिये वित्तीय क्षेत्र को और विकसित बनाने के लिए नीतिगत और विधायी सुधार उपायों की चर्चा की गयी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- वित्तीय बाजार नियामकों के परामर्श के बाद वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना दिसंबर, 2010 में की गयी।
- रघुराम राजन समिति ने 2008 में इस तरह के निकाय के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।
- इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करना और इसे संस्थागत बनाना है।
- नियामकों की स्वायत्तता के पूर्वाग्रह के बिना यह परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर विचार करती है।
- परिषद, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामक समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों पर भी विचार करती है।

- FSDC की गतिविधियों के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।
- परिषद और इसकी उप-समिति परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तावित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श करती है जिसमें मोटे तौर पर वित्तीय स्थिरता, अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास से संबंधित मामले शामिल होते हैं।
- यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान देती है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की संरचना

- **अध्यक्ष** - केंद्रीय वित्त मंत्री।
- **सदस्य** –
  - •वित्तीय क्षेत्र के नियामकों (SEBI, PFRDA, IRDA, और FMC) के प्रमुख।
  - भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर।
  - वित्त सचिव।
  - आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव।
  - वित्तीय सेवा विभाग के सचिव।
  - मुख्य आर्थिक सलाहकार।
  - राजस्व सचिव।
  - इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव।
  - आर्थिक मामलों के विभाग के राज्य मंत्री।
  - भारतीय दिवाला और शोधन
  - अक्षमता बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष।